सुविचार

खुद का अपमान कराके जीने से तो अच्छा मर जाना है क्योंकि प्राणों के त्यागने से केवल एक ही बार कष्ट होता है पर अपमानित होकर जीवित रहने से आजीवन दुःख होता है।

–चाणक्य

हैलो सरकार

जनता की भावनाओं एवं आकांक्षाओं का एकमात्र समाचार-पत्र

पल-पल की टी.वी. एवं रेडियो खबरों के लिए लॉन ऑन करें- www.hellosarkar.com

हैलो सरकार समाचार पत्र में नियमित पाठक बनने, समाचार की प्रति मंगवाने व विज्ञापन देने हेतु सम्पर्क करें
फोनः 0141-2202717
मोः 9214203182
वाट्सप नं. 9928078717

वर्ष-23 | अंक-268 | दैनिक प्रभात संस्करण | जयपुर, सोमवार 02 जून , 2025 | पृष्ठ-4 | मूल्यः 2.50

राम मंदिर में दूसरी बार होगी प्राण प्रतिष्ठा

अपने पूरे परिवार के साथ विराजेंगे राजा राम

लखनऊ। 22 जनवरी 2024 को भगवान श्रीराम बालक राम के रूप में स्थापित किए गए थे। अब दूसरी प्राण प्रतिष्ठा में भगवान राम राजा के रूप में स्थापित किए जाएंगे। राम मंदिर के पहले तल पर राजा राम का दरबार होगा। इस दरबार में भगवान राम उनके अनुज लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, माता जानकी और सेवक हनुमान होंगे। पांच जून के समारोह के लिए राम मंदिर में तैयारियां पूरे जोरशोर से चल रही हैं। अयोध्या पहुंच रहे श्रद्धालुओं में भी भारी उत्साह है। रामलला के दर्शन करने के बाद राजा राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर श्रद्धालु उत्साहित हैं। वहीं, सुरक्षा व्यवस्था के बारे में एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर ने बताया कि रामनगरी फुलप्रूफ सुरक्षा के लिहाज से परिपूर्ण है। जो भी कार्यक्रम स्थल हैं, वहां पर अतिरिक्त सुरक्षा बल लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही जो श्रद्धालु अयोध्या में दर्शन करने आ रहे हैं, उनको भी कोई दिक्कत न होने पाए, इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। राजा राम के साथ सात अन्य उप मंदिरों में भी स्थापित

मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसमें परकोटा के ईशान कोण पर शिवलिंग, अग्नि कोण में प्रथम पूज्य श्रीगणेश, दक्षिणी भुजा के मध्य में महाबली हनुमान, नैरित्र कोण में प्रत्यक्ष देवता सूर्य, वायव्य कोण में मां भगवती, उत्तरी भुजा के मध्य में अन्नपूर्णा माता के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसके साथ ही मुख्य मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार और परकोटा के दक्षिणी पश्चिमी कोने में शेषावतार प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होगी। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के 16 महीने बाद अयोध्या में पूरी तरह से बनकर तैयार भव्य राम मंदिर के एक और प्राण प्रतिष्ठा और अभिषेक समारोह की तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। पिछले साल लोकसभा चुनाव से पहले 22 जनवरी को भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। इस कार्यक्रम में 8000 से अधिक लोगों ने भाग लिया था। इसके मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। इस बार मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। यह कार्यक्रम एक तरह से मंदिर निर्माण का समापन भी होगा, जो पांच अगस्त 2020 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शुरू हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर भवन निर्माण समिति का गठन किया गया था। इसकी कमान प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्र संभाल रहे हैं। राम मंदिर के पहले तल पर राजा राम का दरबार होगा। यहां पर सभी दरवाजे लगा दिए गए हैं। परकोटा के बीच निर्मित छह पूरक मंदिरों व सप्त ऋषियों के सात मंदिरो में भी कपाट लगाने का काम पूरा हो गया है। शिव मंदिर में शिवलिंग की स्थापना का काम चल रहा है। श्रीराम जन्मभूमि के 2.77 एकड़ पर निर्मित राम मंदिर के पहले तल पर भगवान श्रीराम, माता जानकी और उनके तीनों अनुज व हनुमान जी का विग्रह स्थापित किया जा चुका है। इसी की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। राम मंदिर का निर्माण पारंपरिक नागर शैली में किया गया है।

राजस्थान में NIA की बड़ी कार्रवाईपाक जासूसी नेटवर्क से जुड़े संदिग्ध के ठिकाने पर छापा

जयपुर। पाकिस्तान समर्थित जासूसी नेटवर्क को लेकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने राजस्थान में बड़ी कार्रवाई की। एनआईए की टीम ने राज्य के एक अहम ठिकाने पर छापेमारी कर अहम दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सबूत जब्त किए हैं। यह कार्रवाई पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स (PIOs) से जुड़े संदिग्धों की भूमिका की जांच के तहत की गई है।

सूत्रों के मुताबिक, एनआईए को इनपुट मिला था कि राजस्थान में कुछ व्यक्ति पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से संपर्क में हैं और गोपनीय जानकारी साझा कर रहे हैं। इस आधार पर जयपुर सहित अन्य स्थानों पर छापा मारा गया। कार्रवाई के दौरान टीम को कई डिजिटल डिवाइस, संदिग्ध फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से जुड़े कागज़ात और अन्य आपत्तिजनक सामग्री हाथ लगी है।

एनआईए की जांच में सामने आया है कि संदिग्धों को पाकिस्तान से हवाला के जरिये फंडिंग हो रही थी और वे भारत की सामरिक जानकारियां लीक कर रहे थे। यह जासूसी नेटवर्क 2023 से सक्रिय बताया जा रहा है, जिसकी कड़ी

राजस्थान से भी जुड़ती दिख रही है। एनआईए पहले ही इस केस को गंभीर मानते हुए आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 और यूएपीए एक्ट 1967 सहित अन्य धाराओं के तहत दर्ज कर चुकी है। राजस्थान में की गई कार्रवाई को जांच की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

पाक जासूसी केस में 8 राज्यों के 15 ठिकानों पर छापेमारी

पाकिस्तान से जुड़े जासूसी मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने देश के आठ राज्यों में 15 स्थानों पर एक साथ बड़ी छापेमारी की। यह कार्रवाई पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स (PIOs) से जुड़े संदिग्धों के खिलाफ की गई।

एनआईए ने जिन राज्यों में छापे मारे उनमें दिल्ली, महाराष्ट्र (मुंबई), हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, असम और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। कार्रवाई के दौरान टीमों ने संदिग्धों के ठिकानों से कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, संवेदनशील वित्तीय दस्तावेज और अन्य आपत्तिजनक सामग्री जब्त की है। ये सभी सबूत पाकिस्तान के इशारे पर भारत में चल रहे जासूसी नेटवर्क की जांच के तहत खंगाले जा रहे हैं। जांच में सामने आया है कि जिन लोगों के यहां छापे मारे गए, उनके पाकिस्तान स्थित जासूसी नेटवर्क से सीधे संपर्क थे। यह भी पता चला है कि इन लोगों को भारत में जासूसी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए वित्तीय मदद मिल रही थी। एनआईए ने इस केस को 20 मई को दर्ज किया था। इसकी शुरुआत उस आरोपी की गिरफ्तारी से हुई थी, जो 2023 से ही PIOs के साथ मिलकर संवेदनशील सूचनाएं साझा कर रहा था। बदले में उसे भारत के विभिन्न राज्यों में हवाला के जरिए पैसे मिल रहे थे।

पकड़ा गया बिजली माफिया, 700 घरों को दे रखा था अवैध कनेक्शन

कोटा। राजस्थान के कोटा जिले के सुकेत कस्बे में सुरीला वालों की गली में लगभग 700 घरों में बिजली के अवैध कनेक्शन का पर्दाफाश हुआ है। इसके बाद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने, वीसीआर भरकर वसूली करने और जब से सुकेत में विद्युत आपूर्ति शुरू हुई है, तबसे लेकर अब तक की राशि ब्याज सहित वसूल करने के आदेश दिया गया है।

शिकायत पर पर्दाफाश

शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर के रविवार को सुरीला वालों की गली में आयोजित मोहल्ला बैठक के दौरान एक शिकायत मिलने के बाद इस साजिश का पर्दाफाश हुआ। बैठक में स्थानीय लोगों ने कल्लू नामक एक व्यक्ति की ओर से अवैद्य बिजली कनेक्शन देकर अवैध

वसूली की शिकायत की गई। लोगों ने बताया कि कल्लू ने पानी की पाइप लाइन के साथ पाइप डालकर अवैद्य बिजली कनेक्शन दे रखे हैं। प्रत्येक घर से 500 रुपए प्रति महीने वसूल करता है। लगभग 700 घरों में अवैध कनेक्शन हैं।

मौके पर पहुंचे मंत्री

इस पर दिलावर ने अधीक्षण अभियंता विद्युत विष्णु दत्त लोढ़ा को पुलिस दल के साथ मौके पर जाकर कार्रवाई के निर्देश दिए। जिस पर लोढ़ा ने टीम के साथ पहुंचकर अवैध कनेक्शन काटे और केबल जब्त की। इसी बीच दिलावर स्वयं मौके पर पहुंच गए। वहां लोगों ने अंडरग्राउंड पाइप लाइन के जरिए घरों में जा रहे बिजली की अवैध कनेक्शन मंत्री को दिखाए। मंत्री ने तत्काल सुकेत थाना अधिकारी छोटूलाल को बुलाकर आरोपी कल्लू उर्फ जलालुद्दीन तथा उसके सहयोगी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने, वीसीआर भरकर वसूली करने और जब से सुकेत में विद्युत आपूर्ति शुरू हुई है, तबसे लेकर अब तक की राशि ब्याज सहित आरोपी से वसूल करने के आदेश दिया।

इसके बाद दिलावर निरीक्षण करते हुए कुम्हार मोहल्ला पहुंचे, जहां पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुकेत के पुराने भवन पर अतिक्रमण का मामला सामने आया। स्कूल में किए गए अतिक्रमण का मौका मुआयना किया। स्कूल में बने स्टाफ रूम के कक्ष में मवेशी बंधे हुए थे तथा बाकी कमरों पर ताला लगाया हुआ था। मंत्री ने उपखंड अधिकारी को पूरे विद्यालय भवन परिसर को अतिक्रमण मुक्त करने, रिसीवर नियुक्त करने एवं आंगनवाड़ी संचालन के प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

पिंकसिटी प्रेस क्लब के समर कैंप का रंगारंग आगाज, बच्चों को मिलेगा हुनर निखारने का मंच

डे वाई डे सीखने की प्रेरणा

जयपुर। पिंकसिटी प्रेस क्लब ग्रीष्मकालीन बाल अभिरूचि शिविर का जोरदार आगाज रविवार को प्रेस क्लब सभागार में किया गया। समर कैम्प शुभारम्भ के अवसर पर खाद्य एवं सुरक्षा के अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा ने बच्चों की हौसला अफजाई करते हुए बताया कि इस तरह के आयोजन से बच्चों के व्यक्तित्व में सर्वांगीण विकास होता है। उन्होंने प्रतिभागियों को डे वाई डे सीखने की प्रेरणा दी।

10 दिवसीय समर कैम्प शुभारम्भ के अवसर पर प्रेस क्लब अध्यक्ष मुकेश मीणा एवं महासचिव मुकेश चौधरी ने बताया कि बाल अभिरूचि शिविर के माध्यम से क्लब परिवार के बच्चों को विभिन्न विधाओं में पारंगत करना है ताकि वे भविष्य में किसी भी मंच पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा सके।

शिविर में कोषाध्यक्ष विकास शर्मा, उपाध्यक्ष परमेश्वर प्रसाद शर्मा शिविर संयोजक अनिता शर्मा कार्यकारिणी सदस्य निखलेश शर्मा, ज्ञानेन्द्र मिश्रा, विकास आर्य, ओमवीर भार्गव वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह शेखावत, राजकुमार शर्मा, वरिष्ठ रंगकर्मी राजेन्द्र शर्मा राजू सहित अनेक पत्रकार एवं परिजन उपस्थित थे।

दौसा में दिनदहाड़े अपहरण

तेरा बेटा मारा गया..., साइकिल के पास मिली पर्ची ने बढ़ाई दहशत

दौसा। मेहंदीपुर बालाजी के उदयपुरा रोड पर भरत बाल विद्या निकेतन स्कूल के पास रविवार दोपहर करीब डेढ़ बजे पिता को दुकान पर खाना देकर लौट रहे 16 साल के बच्चे का अपहरण हो गया। पिता की दुकान से 300 मीटर दूर बच्चे की साइकिल मिली है। साइकिल के पास एक धमकी लिखी पर्ची भी मिली है, जिसमें लिखा है कि तेरा बेटा मारा गया, 7:30 पर लाश मिलेगी। इस घटना के बाद हड़कंप मच गया लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। बच्चे की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। दौसा डीएसपी रवि प्रकाश शर्मा और बांदीकुई डिप्टी एसपी रोहिताश देवंदा मेहंदीपुर बालाजी पहुंच गए। पिता बलराम ने बताया कि हरिसोना धर्मशाला के सामने उसकी वुडन आइटम की दुकान है। दोपहर करीब 12:30 बजे उसका बेटा शिवम साइकिल से खाना देने आया था। वह 1:00 बजे दुकान से घर के लिए रवाना हुआ था। घर और दुकान के बीच की दूरी करीब एक किलोमीटर है। करीब 20 मिनट बाद भी वह घर नहीं पहुंचा तो परिजन उसे तलाश करने निकले। उदयपुरा रोड पर भरत बाल विद्या निकेतन स्कूल के पास करीब 1:30 बजे शिवम की साइकिल मिली। साइकिल के पास ही कागज का एक छोटा सा टुकड़ा भी पड़ा था। जिस पर लाल मार्कर से लिखा है कि तेरा बेटा मारा गया, 7:30 पर लाश मिलेगी। शिवम राजकीय माध्यमिक विद्यालय मेहंदीपुर बालाजी में पढता है। हाल ही में उसका 10वीं का रिजल्ट आया था। उसके 65 प्रतिशत नंबर आए हैं।

राजस्थान में मंदिर जमीन पर बढ़ते अतिक्रमण से नाराज़ पुजारी, महासंघ ने चेताया आंदोलन का संकेत

दौसा। राजस्थान पुजारी सेवक महासंघ की जिला कार्यकारिणी की बैठक की सहजनाथ महादेव मंदिर पर आयोजित की गई। बैठक में मंदिर माफी की जमीनों पर लगातार हो रहे अतिक्रमण की समस्या के समाधान के लिए आंदोलन की रणनीति बनाने पर चर्चा की गई। इस मामले में कलेक्टर को ज्ञापन देने का निर्णय लिया गया।

प्रदेश अध्यक्ष महंत अरुण शर्मा ने बताया कि विभिन्न तहसीलों में पुजारी पंजिका को ऑनलाइन करवाने के लिए तहसीलदार एवं कलेक्टर को एक साथ आवेदन दिए जाएंगे। देवस्थान विभाग तथा कृषि विभाग द्वारा चल रही योजनाओं को पुजारियो तक पहुंचाने का अधिक से अधिक प्रयास किया जाएगा।

शर्मा ने बताया कि वर्तमान में मंदिर माफी की भूमि पर लगातार अतिक्रमण किया जा रहा है जिस पर राज्य सरकार द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बार-बार ज्ञापन देने के बावजूद भी भूमाफिया के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जिले में ऐसे मामलों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाएगा। यदि कार्रवाई नहीं होगी तो आंदोलन की रणनीति तैयार की जाएगी।

प्रदेश संगठन मंत्री अनिल शर्मा ने बताया कि जिले में बहुत से पुजारियों का नाम देवस्थान विभाग में तथा तहसीलों के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने के कारण उन्हें बहुत दिक्कत आ रही है। इसका कैंप लगा कर आवेदन लिए जाएंगे और समस्याओं का समाधान करवाया जाएगा।

नगर अध्यक्ष महंत रामेश्वर प्रसाद शर्मा ने बताया कि पुजारी पंजिका को ऑनलाइन दर्ज करने की कार्रवाई के आदेश के बावजूद भी तहसीलों में पुजारियो को परेशान होना पड़ रहा है। इसके लिए कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाएगा।

बैठक में नरसिंह मंदिर के महंत विमल शर्मा को जिला प्रभारी एवं महंत योगेश शर्मा को जिला संगठन महामंत्री का पद सर्व सम्मति से प्रदान किया गया। एवं पंडित कैलाश शर्मा को सैंथल तहसील प्रभारी तथा वीरेंद्र शर्मा को सह प्रभारी, पंडित सुरेश पुजारी को बांदीकुई एवं बसवा तहसील प्रभारी, महंत कैलाश शर्मा को महुआ तहसील प्रभारी, पंडित राजेंद्र शर्मा एवं कपिल शर्मा को लवाण तहसील प्रभारी, महंत पवन शर्मा बारादरी को दोसा तहसील प्रभारी बनाया गया। सभी पदाधिकारियों का माला एवं साफा पहनाकर स्वागत किया।

देवालयों से अब नशा मुक्ति का संदेश, जयपुर में चला व्यसन मुक्त संकल्प अभियान

जयपुर। छोटीकाशी के सभी प्रमुख देवालयों से अब व्यसन मुक्ति का संदेश भी दिया जाएगा। मंदिर के महंत-पुजारी भक्तों को सभी तरह के नशों से बचने की प्रेरणा देंगे। इस आशय का निर्णय रविवार को विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के उपलक्ष्य में रविवार को गोविंद देवजी मंदिर में महंत अंजन कुमार गोस्वामी के सान्निध्य और स्वामी अवधेशाचार्य महाराज की अध्यक्षता में हुए व्यसन मुक्त जयपुर संकल्प समारोह में लिया गया। मंदिर श्री गोविंद देवजी प्रबंधन के मार्गदर्शन में अखिल विश्व गायत्री परिवार, जयपुर की अगुवाई में हुए आयोजन में नशा मुक्ति के क्षेत्र में कार्य कर रही संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने सामूहिक रूप से नशा मुक्त जयपुर अभियान चलाने का निर्णय लिया। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं ने दर्शनार्थियों के समक्ष झोली फैलाकर तम्बाकू उत्पादों का दान करने की याचना की। लोगों से बीड़ी, सिगरेट, गुटखा सहित अन्य नशीले उत्पाद की भीख मांगी तो कई लोगों ने गुटखा और पान मसाला झोली में डाले। तम्बाकू का सेवन छोडने वालों और नशा मुक्ति के क्षेत्र में कार्य कर रहे विशिष्टजनों का सम्मान किया गया। पंच कुंडीय व्यसन मुक्ति महायज्ञ और व्यसन मुक्त जयपुर संकल्प समारोह के मुख्य अतिथि सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा थे। उन्होंने कहा कि जल्द ही प्रदेश नशा मुक्त होगा।

सरकार ने इस दिशा में कार्य शुरू कर दिया है। शीघ्र ही इसके परिणाम मिलेंगे। गायत्री परिवार

राजस्थान जोन के प्रभारी ओमप्रकाश अग्रवाल ने अतिथियों का स्वागत किया।

मुख्य वक्ता इंडियन अस्थमा केयर सोसायटी के सचिव धर्मवीर कटेवा ने कहा कि गुलाबी नगरी को गुटखा और पान खाकर लोग गंदा करने से बाज आएं। सनातन बोर्ड संघर्ष समिति के संयोजक राहुल द्विवेदी और सर्वेश्वर शर्मा, समाजसेवी और रति फाउंडेशन से रीना भार्गव, राजस्थान प्रदेश नशाबंदी समिति के कर्मवीर कटेवा,इंडियन अस्थमा केयर सोसायटी के सचिव धर्मवीर कटेवामानव सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष कौशल सत्यार्थी, राजस्थान समग्र सेवा संघ के ताराचंद थाकन, समाजसेवी रीना भार्गव को नशा मुक्ति आंदोलन पुरोधा सम्मान से सम्मानित किया गया। प्रारम्भ में ठाकुर श्री राधा गोविंद देवजी, वेदमाता गायत्री और गुरु सत्ता के पूजन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। गायत्री शक्तिपीठ ब्रह्मपुरी के व्यवस्थापक सोहन लाल शर्मा, सह व्यवस्थापक मणिशंकर पाटीदार के निर्देशन में आचार्य पीठ से दिनेश आचार्य और गायत्री कचोलिया ने व्ययन मुक्ति प्रज्ञागीतों के साथ पंच कुंडीय व्यसन मुक्ति महायज्ञ करवाया।

पूर्णाहुति में सभी को नशा कर रहे लोगों का नशा छुड़ाने का संकल्प करवाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए स्वामी अवधेशाचार्य महाराज ने उपस्थित सभी लोगों को हाथ आगे कर कभी भी नशा नहीं करने और 10 लोगों का नशा छुड़ाने की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि नशा छुड़वाने के लिए सभी मंदिर प्रबंधन को आगे आना चाहिए। इस मौके पर गायत्री चेतना केन्द्र मुरलीपुरा की ओर से गोविंद देवजी मंदिर परिसर में नशा मुक्ति प्रदर्शनी भी लगाई गई।

सभी तरह के नशों से निजात दिलाने के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों और काउंसलर ने सेवाएं दी। जरुरतमंदों को निशुल्क दवाएं दीं गई। संतों महंतों की अगुवाई में निकाली गई व्यसन मुक्ति रैली के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।

संतों-महंतों का मिला सान्निध्य

गोविंद देवजी मंदिर में महंत अंजन कुमार गोस्वामी के सान्निध्य में आयोजित कार्यक्रम में स्वामी अवधेशाचार्य महाराज, स्वामी राघवेन्द्र, श्री सरस निकुंज के प्रवीण बड़े भैया, मनु महाराज, पं. राजकुमार चतुर्वेदी, महंत संजय गोस्वामी सहित विभिन्न मंदिरों के संत-महंत उपस्थित थे।

आसरा फाउंडेशन जयपुर ने तम्बाकू निषेध जागरूकता का चलाया अभियान

जयपुर। विश्व तम्बाकू निषेध दिवस पर गिरधरिपुरा में आसरा फाउंडेशन द्वारा जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। गौरतलब है कि एनजीओ आसरा फाउंडेशन जयपुर ने विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के अवसर पर गिरधरिपुरा क्षेत्र में एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्देश्य तम्बाकू सेवन के दुष्प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक करना और नशा मुक्त जीवन शैली को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम में स्थानीय महिलाओं और बच्चों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता पंकज एवं आरती ने तम्बाकू से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं और इससे छुटकारा पाने के उपायों पर जानकारी साझा की। वहीं, सोनू धाकड़ ने विशेष रूप से बच्चों को तम्बाकू से दूर रहने के महत्व को सरल व प्रभावी ढंग से समझाया। कार्यक्रम में Law Interns ने भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई और उपस्थित लोगों को तम्बाकू मुक्त जीवन की शपथ दिलवाई। कार्यक्रम के अंत में महिलाओं को सैनेटरी नैपकिन और बच्चों को बिस्किट वितरित किए गए। यह आयोजन सामाजिक जागरूकता की दिशा में एक सराहनीय प्रयास रहा।

रामसेतु राष्ट्रीय धरोहर स्मारक घोषित हो

(लेखक- संजय गोस्वामी)

इसरो के जोधपुर और हैदराबाद राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थानों के वैज्ञानिकों ने रामेश्वरम द्वीप और रामसेतु के निर्माण का श्रेय प्राकृतिक भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को दिया है, जिसमें टेक्टोनिक गतिविधि, वायु क्षरण और समुद्री क्रियाएं शामिल हैं। पैलियोग्राफिक साक्ष्य संकेत देते हैं कि लगभग 6,000 से 7,000 साल पहले, पंबन के पास समुद्र का स्तर अपने वर्तमान स्तर से लगभग 17 मीटर नीचे था; लगभग 10,000 साल पहले, यह लगभग 60 मीटर कम था; और लगभग 20,000 साल पहले अंतिम हिमनद के दौरान, समुद्र का स्तर वर्तमान स्तरों से लगभग 120 मीटर नीचे था। इस सिद्धांत के अनुसार कि रामसेतु प्राकृतिक रूप से बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और मिट्टी के अवसादन से उत्पन्न हुआ था, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) का मानना था कि धनुषकोडी और थलाइमन्नार 2003 में, इसरो के समुद्री और जल संसाधन समूह ने भारतीय रिमोट सेंसिंग उपग्रहों के डेटा का विश्लेषण किया - विशेष रूप से, आईआरएस-पी4 (अप्रैल 2002) से महासागर रंग मॉनिटर डेटा और आईआरएस-1डी (मार्च-मई 2000) से लिस-III डेटा - यह जांचने के लिए कि क्या राम सेतु मानव निर्मित था या प्राकृतिक कोरलीन संरचना थी। यह परिकल्पना की गई थी कि 103 छोटे, रैखिक पैच रीफ से बना यह पुल कार्बनिक कोरलीन जमा को ओवरले करता है। इसका रैखिक आकार बताता है कि भारतीय प्रायद्वीप कभी श्रीलंका से जुड़ा था। हालांकि, नासा की छवियों की वैकल्पिक व्याख्याओं ने राजनीतिक और धार्मिक दृष्टिकोण पेश किए, कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि राम सेतु कृत्रिम रूप से बनाया गया था नासा के अधिकारी मार्क हेस ने कहा कि द्वीपों की श्रृंखला की उत्पत्ति या आयु के बारे में कोई प्रत्यक्ष जानकारी नहीं है, न ही यह कि उनके निर्माण में मनुष्यों की कोई भूमिका थी। नल और नील दोनों रामायण काल के बड़े इंजीनियर थे. उन्होंने जांच मुआयना और सर्वे के बाद समुद्र पर पत्थर बिछाकर ये पुल बांधा था राम सेतु निर्माण में हनुमान ने नल और नील को हर पत्थर पर राम का नाम लिखने में मदद की, ताकि पत्थर आपस में चिपक जाएं और पुल मजबूत रहे. रावण की हार और राम की वानर सेना से जुड़े युद्ध के समापन के बाद, उन्होंने क्या किया? अगर पूछा जाए कि समुद्र पर देश का पहला बड़ा पुल किसने बनाया, तो सबूतों के आधार पर जवाब होगा राम सेतु। अगर वानर सेना के दो इंजीनियर वानरों नल और नील ने रामसेतु नहीं बनाया होता है तो श्रीराम के लिए अपनी सेना को लंका तक पहुंचाना मुश्किल हो जाता. भारतीय न्यायालयों में दायर याचिकाओं के हिस्से के रूप में प्रस्तुत की गई छवियों ने यह सुझाव देते हुए सबूत प्रदान किए कि राम सेतु न केवल एक मानव निर्मित संरचना से बनाया गया है, बल्कि यह लगभग 1.75 मिलियन वर्ष पुराना है, जो कि त्रेता युग में भगवान राम के काल (भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार) के दौरान हुआ था।यह कोई छोटी संरचना नहीं थी; यह कई किलोमीटर तक फैली हुई थी। हालाँकि उस समय औपचारिक रूप से इंजीनियरिंग नहीं पढ़ाई जाती थी, लेकिन नल और नील ने यह कारनामा कर दिखाया। सैटेलाइट इमेज, वैज्ञानिक अध्ययन और चल रही जांच सभी रामेश्वरम से श्रीलंका तक फैले एक पुल के अस्तित्व का समर्थन करते हैं, जिसमें समुद्र के नीचे पत्थरों की एक स्पष्ट रेखा दिखाई देती है। यह समय-सीमा होमो सेपियंस की उत्पत्ति के साथ मेल नहीं खाती है, जो लगभग 200,000 साल पहले विकसित हुई थी, न ही लगभग 100,000 साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप पर पहली बस्तियों के साथ। कई द्वीप श्रृंखलाएँ और समुद्री पहाड़ियाँ - जैसे कि फिलीपींस और जापान में सबडक्शन-ज़ोन ज्वालामुखी के परिणामस्वरूप, हवाई द्वीप लिथोस्फेरिक आंदोलन के कारण, आइसलैंडिक मध्य-महासागर लकीरें, सेंट हेलेना के पास परिवर्तन दोष, और कैरिबियन और लैटिन अमेरिका में समुद्री अवसादन - भूवैज्ञानिक इतिहास में सामान्य विशेषताएं हैं। इनमें से कई समुद्री संरचनाएँ बेसाल्टिक हैं, जो आग्नेय गतिविधि के ठंडा होने से बनी हैं। इसके विपरीत, राम सेतु में किसी भी ज्ञात आग्नेय या ज्वालामुखीय आधार का अभाव प्रतीत होता है। मद्रास विश्वविद्यालय में प्राकृतिक खतरों और आपदा अध्ययन केंद्र के वी. राम मोहन के अनुसार, पुल के लिए भूवैज्ञानिक स्पष्टीकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित हैं, प्रचलित सिद्धांत यह है कि बढ़ी हुई तलछट या समुद्र तल सहसंबंध सबसे प्रशंसनीय स्पष्टीकरण प्रदान करता है। मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति एस. रामचंद्रन ने उल्लेख किया कि राम सेतु में देखी गई गतिशील तलछट प्रक्रियाएँ अटलांटिक तट के साथ आम हैं। इसके अलावा, प्रसिद्ध भूविज्ञानी एन. रामानुजम ने बताया कि पुल का निर्माण भारतीय प्लेट के अपने दक्षिणी क्षेत्रों से अलग होने, यूरेशियन भूभाग से टकराने और उसके बाद टेक्टोनिक गतिविधि और तलछट के कारण हुआ - जिसका एक परिणाम कावेरी बेसिन है। इस प्रक्रिया के कारण रिज संरचनाओं का विकास हुआ, जिसके बाद कोरल और एटोल संरचनाएँ बनीं, जिसने धनुषकोडी और थलाइमन्नार स्पिट्स से जमा को आकर्षित किया, जिससे राम सेतु के लघु द्वीपों जैसे पनडुब्बी शोल का निर्माण हुआ। यह जटिल विद्वतापूर्ण व्याख्या भारतीय जनता के लिए काफी पेचीदा थी। 2007 की शुरुआत में, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के समर्थन से, भारत सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में एक हलफनामा प्रस्तुत किया जिसमें कहा गया कि रामसेतु अंततः ज्वार की क्रिया और अवसादन के परिणामस्वरूप एक प्राकृतिक संरचना थी। कोरल की उपस्थिति के आधार पर, एएसआई ने तर्क दिया कि संरचना मानव निर्मित नहीं थी और इसलिए, इसे ऐतिहासिक या पुरातात्विक स्मारक के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। नतीजतन, इस प्राचीन संरचना को चटर्जी-एडम ब्रिज विनियमों के तहत एक स्मारक के रूप में संरक्षण के लिए अयोग्य माना गया हालांकि, सितंबर में सरकार ने न्यायालय से हलफनामा वापस ले लिया। संस्कृति मंत्रालय ने हलफनामे में कम से कम तीन खंडों को हटाने का सुझाव दिया था, जिन्हें पवित्र हिंदू मान्यताओं के विपरीत माना जा सकता था; लेकिन हलफनामे को प्रस्तुत किए जाने से पहले उनमें से केवल दो को हटाया गया। हटाए नहीं गए खंडों में से एक रामायण की ऐतिहासिकता की कमी से संबंधित था, जिसने जल्द ही विवाद को जन्म दे दिया। संस्कृति मंत्री ने इस मामले पर अपना इस्तीफा दे दिया, जबकि वाणिज्य मंत्री, जो उसी राजनीतिक गुट से हैं, ने कहा कि यदि वे संबंधित विभाग के प्रमुख होते तो वे भी इस्तीफा दे देते। हिंदू मुन्नानी नामक एक धार्मिक समूह सेतुसमुद्रम परियोजना के विरोध में रामसेतु को राष्ट्रीय पुरातात्विक धरोहर के रूप में सूचीबद्ध करने की मांग कर रहा है। 2007 में, मद्रास उच्च न्यायालय ने हिंदू मुन्नानी द्वारा दायर तीन याचिकाओं को सर्वोच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप सेतुसमुद्रम परियोजना को स्थगित कर दिया गया। भारतीय पुरातत्व संस्थान (एएसआई), विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के रूप में, वैज्ञानिक तरीकों की वकालत करता है और पौराणिक मान्यताओं से खुद को दूर रखता है। इसने तर्क दिया कि वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास की रामायण और अन्य पौराणिक ग्रंथ निस्संदेह भारतीय साहित्य का एक प्राचीन हिस्सा हैं, लेकिन उन्हें ऐतिहासिक अभिलेख नहीं कहा जा सकता है जो निर्विवाद रूप से पात्रों के अस्तित्व या उनमें घटनाओं की घटना को साबित करते हैं। हालांकि, लीग के सदस्यों और समर्थकों के विरोध के सामने, सरकार ने भगवान राम की धार्मिक ऐतिहासिकता और हिंदू धर्म में उनके महत्व को कायम रखते हुए समझौता करने की कोशिश की। हलफनामा तैयार करने वाले भारतीय सामाजिक अनुसंधान संस्थान के दो सदस्यों को सुप्रीम कोर्ट से वापस लेने के बाद निलंबित कर दिया गया था। धर्मनिरपेक्ष टिप्पणीकार प्रफुल बिदवई उन कई लोगों में से एक थे जिन्होंने सरकार की आलोचना की थी कि यह दृष्टिकोण स्वीकार करना कि आस्था को हमेशा इतिहास, पुरातत्व और यहां तक कि भूविज्ञान पर हावी होना चाहिए - जो एडम ब्रिज जैसी प्राकृतिक संरचनाओं के अस्तित्व की व्याख्या करता है - और यह स्वीकार करना कि परियोजना को तथ्यों के बजाय मिथकों और शास्त्रों के कारण रद्द कर दिया जाना चाहिए। दिसंबर 2008 में, इमेजेस ऑफ इंडिया नामक एक सरकारी प्रकाशन संसद में पेश किया गया था। भारत की राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी द्वारा प्रकाशित, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष जी. माधवन नायर की प्रस्तावना के साथ, यह पुस्तक एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है, जो पिछली ज्ञान-मीमांसा संबंधी विनम्रता को पलटते हुए मौन रूप से इस दावे का समर्थन करती है कि पुल मानव निर्मित हो सकता है।जिसकी प्रतिध्वनि प्राचीन भारतीय पौराणिक महाकाव्य, रामायण में है वाक्यांश महाकाव्य से संबंध दर्शाता है। जब शोध चल रहा था, एक पुस्तक ने दावा किया कि पुल को भारतीय पौराणिक कथाओं से जुड़े प्राचीन इतिहास के उदाहरण के रूप में देखा जाता है । इसके बाद, भाजपा प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर (बाद में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री नियुक्त) ने कहा कि विज्ञान ने कांग्रेस की राजनीति पर विजय प्राप्त की है, और सरकार अब केवल भगवान राम को ही नहीं बल्कि राम सेतु को भी स्वीकार करने के लिए मजबूर है। विवाद पर बाद में टिप्पणी करने वाली निवेदिता मेनन ने इस बात पर प्रकाश डाला कि जबकि भारतीय राज्य लगातार धर्मनिरपेक्षता का हवाला देकर धार्मिक आस्था को वैज्ञानिक तथ्यों के खिलाफ खड़ा करता है, हिंदू दक्षिणपंथी वास्तव में इस बात पर जोर दे रहे थे कि संरचना मानव निर्मित थी और इसलिए ऐतिहासिक साक्ष्य के अधीन थी, ठीक इसलिए क्योंकि यह पौराणिक नहीं थी; यह प्राकृतिक नहीं है, भगवान द्वारा बनाई गई है। धार्मिक प्रदर्शनकारियों और धर्मनिरपेक्षतावादियों दोनों के लिए, मोक्ष विज्ञान पर निर्भर प्रतीत होता था। जबकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने कहा कि रामायण राम सेतु के प्रमाण के रूप में काम नहीं करती है, भाजपा भगवान के पदचिन्हों पर चलती रही, कभी-कभी विज्ञान का हवाला देती रही, और सरकार ने भी देवता के नाम का जप किया। इस बीच, वैज्ञानिकों और तर्कवादियों के एक नए समूह ने तमिलनाडु तट पर पारिस्थितिक आपदा की आशंका जताते हुए सेतुसमुद्रम परियोजना का विरोध करना शुरू कर दिया। सेतुसमुद्रम और चूना पत्थर के टीलों को ध्वस्त करने के कुछ मुखर समर्थक भी पारिस्थितिक आधार पर परियोजना के खिलाफ चेतावनी दी । एडम्स ब्रिज 2004 की सुनामी के प्रकोप को रोकने के लिए एक किले के रूप में काम कर सकता था, जिसने दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के बड़े हिस्से को तबाह कर दिया था। हालाँकि इस समूह ने पुल की पवित्र पौराणिक कथाओं को बड़े पैमाने पर खारिज कर दिया, इसे एक प्राकृतिक संरचना के रूप में देखा और पारिस्थितिक विचारों पर जोर दिया, इस दृष्टिकोण ने पुल के धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों दृष्टिकोणों को प्रभावित किया, जैसा कि अप्रैल 2008 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में परिलक्षित होता है। सेतुसमुद्रम का विरोध करने वाले धार्मिक प्रदर्शनकारियों से अदालत के सवालों ने पुल की पवित्र स्थिति को स्वीकार करने या अस्वीकार करने की जटिलता को उजागर किया। पीठ ने पूछा, समुद्र के बीच में कौन पूजा करता है? इसका तात्पर्य यह है कि यदि यह कभी साबित हो गया - या हो सकता है - कि पुल अनुष्ठानों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक पवित्र भूमि थी, तो यह रामायण की ऐतिहासिकता के प्रमाण के रूप में भी काम कर सकता है।

संपादकीय

दुखद घटना

हरियाणा के पंचकूला में उत्तराखंड से आए एक परिवार की सामूहिक आत्महत्या ने हर संवेदनशील व्यक्ति को गहरे तक झकझोर कर रख दिया। एक कार में नाकाम बेटे ने मां-बाप,पत्नी, दो किशोर बेटियों व एक बेटे के साथ जहर खाकर आत्महत्या कर ली। पूरे परिवार के खत्म होने के बाद कुछ समय के लिए जीवित बचे व्यक्ति ने चश्मदीद को बताया कि वह कर्ज में डूब गया था, कोई रास्ता नजर न आता देख सामूहिक आत्महत्या का निर्णय लिया। पुलिस के पहुंचने व चिकित्सीय प्रयासों के बावजूद परिवार में किसी व्यक्ति को बचाया नहीं जा सका। निश्चय ही यह दुखद घटना हर इंसान को उद्वेलित करती है। लेकिन यह भयावह घटना तमाम सवालों को जन्म देती है। आखिर इंसान कैसे सोच लेता है कि आत्महत्या कर लेना संकट का अंतिम समाधान है? जब व्यक्ति में जोखिम से उपजे संकट से जूझने का सामर्थ्य नहीं है तो भारी कर्जा उठाना कितना तार्किक है? महत्वपूर्ण सवाल यह भी कर्ज से हारे व्यक्ति को ये अधिकार किसने दे दिया कि वो अपने साथ दो पीढ़ियों को सदा के लिये खत्म कर दे? कैसे कोई व्यक्ति अपनी नाकामी की सजा मां-बाप, पत्नी व बच्चों को दे सकता है? यह कल्पना करनी भी भयावह है कि अपना अधिकांश जीवन जी चुके मां-बाप, तीन बच्चों को जन्म देने वाली मां तथा सुखी भविष्य की कल्पना के साथ जीवन की पारी की शुरूआत करने वाले बच्चों ने जहर खाना सहज स्वीकारा होगा। यदि उन्हें यह जहर बिना बताए भी दिया गया होगा तो भी जहर की पीड़ा ने उन्हें तड़फाया भी होगा। अकसर ऐसे मामलों में पूरे परिवार को मौत की राह में ले जाने वाले आत्मघाती व्यक्ति के मन में यह भय भी होता है कि उसके जाने के बाद उसके परिवार का क्या होगा? कहीं उसके लिये कर्ज की सजा परिवार को तो नहीं मिलेगी? निस्संदेह, एक परिवार का यूं जहर खाकर आत्महत्या करना हमारी सामाजिक व्यवस्था में आई विद्रूपताओं की ओर इशारा करता है। जिस भी बैंक या व्यक्ति से आत्महत्या करने वाले परिवार के मुखिया ने कर्ज लिया था, निश्चय ही वहां से उसे किसी भी तरह की राहत की उम्मीद नजर नहीं आई होगी। लेकिन सवाल उठता है कि क्या उसे अपने मित्रों व रिश्तेदारों से भी किसी राहत की उम्मीद नहीं थी? कहा जाता है कि पड़ोसी व मित्र ही संकट के समय में मददगार होते हैं। तो क्या माना जाना चाहिए कि आज हमारे रिश्ते महज दिखावे के रह गए हैं? आखिर विवाह समारोह समेत तमाम अवसरों पर जुटने वाली लोगों की भीड़ केवल महज खाने-पीने तक की ही दोस्त होती है? क्या नैतिक दायित्व नहीं बनता कि संकट में फंसे व्यक्ति के नाते रिश्तेदार या मित्र मदद करें? बहरहाल, गत सोमवार को घटी घटना के सभी तथ्य सामने आने में अभी वक्त लगेगा और घटनाक्रम से जुड़ी अन्य जानकारियां भी सामने आएंगी। लेकिन यह एक हकीकत है कि एक कर्ज से हारा हंसता-खेलता परिवार हमेशा-हमेशा के लिये चिरनिद्रा में सो गया है। लेकिन यह दुखांत हमें कई सबक दे गया है। पहला तो यही कि हमें कर्ज उसी सीमा तक लेना चाहिए, जिस सीमा तक हम चुकाने की सामर्थ्य रख सकें। कोई भी जोखिम यदि हम व्यापार में उठाएं तो उसके तमाम नकारात्मक पहलुओं पर जरूरी विचार करें। उसके बुरे से बुरे परिणाम के बारे में आकलन करें। दूसरा सबक यह है कि हमारे सामने संकट कितना भी बड़ा क्यों न हो, हमें हार नहीं माननी चाहिए। यह भी कि खुद व परिवार को मौत के मुंह में धकेलना किसी समस्या का समाधान नहीं है। आज की पीढ़ी जल्दी मोटा मुनाफा कमाने की होड़ में बड़े कर्ज लेकर दांव तो खेलती है,लेकिन जरूरी नहीं हर जोखिम लाभदायक ही साबित हो।

बढ़ती आबादी को ताकत बनाने की जरूरत

मोहन गुरुस्वामी

उन्नत देशों की बुजुर्ग आबादी के अनुभवों के आधार पर हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि वृद्धों की बढ़ती संख्या के लिए हमें कराधान, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य देखभाल संबंधित अपनी नीतियों में समुचित योजनाएं बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। वृद्धों की संभाल पर खर्चा अधिक होता है। चिंता की बात है कि देश में जनसंख्या की विशालता से मिलने वाला लाभ कहीं आबादी से बना दुःस्वप्न बनकर न रह जाए। लंबे समय से जनसंख्या के आंकड़ों के हिसाब से मिलने वाले फायदे-नुकसानों के बारे में बोलता-लिखता आया हूं। राजनेता और उनके दलाल यह जाने बिना कि शब्दों का अर्थ क्या है, इसको लपक कर दोहराने लगते हैं। चुनौतियां हमारे सामने हैं। वह भारत, जिसकी जनसंख्या 134 करोड़ है, अब विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला राष्ट्र है। लेकिन भारत हमेशा इतना बड़ा नहीं था, जितना कि आज है, चाहे यह जनसंख्या हो या अर्थव्यवस्था। वर्ष 1921, जिसे 'विभाजन का बड़ा साल' कहा जाता है, भारत के जनसांख्यिकीय इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस साल मृत्यु दर में काफी गिरावट आई और जनसंख्या वृद्धि की दर अपेक्षाकृत स्थिर रहने वाली लीक से हटकर तेजी से बढ़ने होने की शुरुआत हुई। वर्ष 1801-1921 के बीच जनसंख्या वृद्धि की रफ्तार काफी धीमी रही, लगभग 20 करोड़ से 22 करोड़ होना। लेकिन 1921 के बाद से हमारी जनसंख्या बढ़ोतरी वास्तव में आज आकाश को छूने की कगार पर है। जनसंख्या में वृद्धि 1981 में 2.22 प्रतिशत की उच्चतम दर को छू गई थी, उसके बाद से बढ़ोतरी दर घटने की ओर है। एक सदी की अवधि के अंदर, भारत की जनसंख्या में छह गुना इजाफा हुआ। अनुमान बताते हैं कि भारत में पिछले सौ वर्षों में लगभग 200 मिलियन लोग जुड़े और वर्तमान सदी के मध्य तक 200 मिलियन और लोग जुड़ने की उम्मीद है। भिन्न अनुमानों का मध्य आंकड़ा बताता है कि वर्ष 2005-50 के बीच, भारत की जनसंख्या में लगभग 45 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। वृद्ध जनसंख्या (65 वर्ष से अधिक उम्र वाले) का अनुपात 2050 में 5 प्रतिशत से बढ़कर 14.5 प्रतिशत हो जाएगा, संख्या के मुताबिक कहें तो इनकी गिनती 5.7 करोड़ से बढ़कर 24 करोड़ हो जाएगी। उन्नत देशों की बुजुर्ग आबादी के अनुभवों के आधार पर हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि वृद्धों की बढ़ती संख्या के लिए हमें कराधान, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य देखभाल संबंधित अपनी नीतियों में समुचित योजनाएं बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। वृद्धों की संभाल पर खर्चा अधिक होता है। चिंता का एक अन्य बड़ा पहलू है बढ़ता जनसंख्या घनत्व। अनुमान है कि जहां यह 2005 में 345 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, 2050 में बढ़कर 504 प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। बढ़ते शहरीकरण के चलन के साथ इसे जोड़कर देखने पर, आने वाले सालों में समस्याओं में इजाफे का संकेत मिलता है। साल 2000 में, कुल आबादी का केवल 28.7 प्रतिशत या लगभग 30 करोड़ लोग शहरी क्षेत्रों में बसे हुए थे; अब अनुमान है कि 2030 तक यह संख्या कुल आबादी की 40.7 प्रतिशत या लगभग 60 करोड़ हो जाएगी। इस भारी वृद्धि में विशेष रूप से मध्यम और कामकाजी वर्ग की बढ़ती आर्थिक शक्ति की भूमिका है। इसके मद्देनजर, पर्याप्त रूप से उन्नत आवास एवं शहरी बुनियादी ढांचा, मसलन, जल, सीवरेज, जन सुविधाएं, तीव्र गति परिवहन, यातायात प्रबंधन एवं पार्किंग, ऊर्जा और दूध एवं दुग्ध उत्पाद, प्रसंस्कृत खाद्य व बागवानी उत्पाद जैसे भोज्य पदार्थों की अधिक खपत और उनके कुशल वितरण के लिए प्रावधान करने की आवश्यकता पड़ेगी। अनुमान है कि 15-64 वर्ष आयु वर्ग की गिनती जो कि 2005 में कुल आबादी का 62 प्रतिशत थी, 2050 में बढ़कर लगभग 67.3 प्रतिशत हो जाएगी, संख्या के हिसाब से कहें, तो 70 करोड़ से 112 करोड़ होना। फिलहाल भारत में हर साल कामकाजी वर्ग में 1 करोड़ 20 लाख लोग जुड़ रहे हैं। इस आयु वर्ग में वृद्धि 2030 तक तेज रहेगी, जिसके बाद से इसमें शुरू हुई गिरावट इस स्तर पर पहुंच जाएगी कि 2045-50 के बीच शायद ही कोई वृद्धि हो, जो कि 15-64 जनसंख्या समूह की संख्या में स्थिरीकरण और उसके बाद से इसके बढ़ाते जाने का संकेत है।

यह चक्र प्राकृतिक है क्योंकि जनसंख्या वृद्धि में ठहराव आता रहता है। अगले तीन दशकों की तात्कालिक चुनौती है, पहले करोड़ों नौकरियों का सृजन करना और फिर श्रमिकों की उपलब्धता में तेज गिरावट से निपटना। जैसा कि हाल-फिलहाल चीन को अनुभव करना पड़ रहा है। जनसांख्यिकीय परिभाषा में जनसंख्या स्थिरीकरण का अर्थ है एक निश्चित समयावधि में जन्म और मृत्यु दर एक समान रहना। अधिक बारीकी से कहें तो, यदि किसी आबादी की प्रजनन दर 2.1 हो जाए, तो उसे जनसंख्या स्थिर होने की संज्ञा दी जाती है। एनपीपी 2000 में परिकल्पना की गई थी कि वर्ष 2045 तक भारत को जनसंख्या स्थिरीकरण बनाना पड़ेगा। यह लक्ष्य इस धारणा पर आधारित है कि देश को वर्ष 2010 तक जनसंख्या का प्रतिस्थापन स्तर टीएफआर 2.1 तक ले आना चाहिए था। हम यह पाने में चूक गए। हालांकि टीएफआर के हालिया आंकड़े 2045 तक भी इस लक्ष्य की प्राप्ति न हो पाने का संकेत दे रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय अब जनसंख्या स्थिरीकरण पाने के वास्ते वर्ष 2060 को एक संभावित लक्ष्य के रूप में देखने लगा है। यहां पर यह उल्लेख करना उचित होगा कि जनसंख्या स्थिरीकरण, प्रतिस्थापन प्रजनन क्षमता (यानी जितने मरें, उतने पैदा हों) बनने के बहुत बाद जाकर बनता है। वर्ष 1996 में योजना आयोग द्वारा गठित 'जनसंख्या पर तकनीकी समिति' द्वारा किए गए एक अध्ययन में अनुमान लगाया गया था कि भारत 2026 तक प्रतिस्थापन स्तर की प्रजनन दर प्राप्त कर पाएगा। लेकिन, हिंदी भाषी राज्यों में यह बिहार में 2039 तक, राजस्थान 2048 तक, मध्य प्रदेश 2060 से आगे और उत्तर प्रदेश में 2100 के बाद ही संभव होगा। हमें 2060 या 2070 से पहले राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरीकरण पाने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ये क्षेत्रीय असमानताएं इन राज्यों में अनुमानित जनसंख्या में खतरनाक वृद्धि के रूप में फलीभूत होंगी। 1991-2050 के दौरान भारत की जनसंख्या में होने वाली 77.3 करोड़ की वृद्धि में अकेले उत्तर प्रदेश का हिस्सा 19.8 करोड़ रहेगा।

(चिंतन-मनन)

विनम्रता का पाठ

चिंतन मनन

पंडित विद्याभूषण बहुत बड़े विद्वान थे। दूर-दूर तक उनकी चर्चा होती थी। उनके पड़ोस में एक अशिक्षित व्यक्ति रहते थे-रामसेवक। वे अत्यंत सज्जन थे और लोगों की खूब मदद किया करते थे। पंडित जी रामसेवक को ज्यादा महत्व नहीं देते थे और उनसे दूर ही रहते थे। एक दिन पंडित जी अपने घर के बाहर टहल रहे थे। तभी एक राहगीर उधर आया और मोहल्ले के एक दुकानदार से पूछने लगा-भाई यह बताओ कि पंडित विद्याभूषण जी का मकान कौन सा है। यह सुनकर पंडित जी की उत्सुकता बढ़ी। वह सोचने लगे कि आखिर यह कौन है जो उनके घर का पता पूछ रहा है। तभी दुकानदार ने उस राहगीर से कहा-मुझे तो किसी पंडित जी के बारे में नहीं मालूम। तब राहगीर ने कहा-क्या रामसेवक जी का घर जानते हो?

दुकानदार ने हंसकर कहा-अरे भाई उन्हें कौन नहीं जानता। वे बड़े भले आदमी हैं। फिर उसने हाथ दिखाकर कहा- वो रहा रामसेवक जी का घर। फिर दुकानदार ने राहगीर से सवाल किया-लेकिन आपको काम किससे है? पंडित जी से या रामसेवक जी से? राहगीर कहने लगा-भाई काम तो मुझे रामसेवक जी से है। पर उन्होंने ही बताया था कि उनका मकान पंडित विद्याभूषण जी के पास है। यह सुनकर पंडित जी ग्लानि से भर उठे। सोचने लगे कि उन्होंने हमेशा ही रामसेवक को अपने से हीन समझा और उसकी उपेक्षा की पर रामसेवक कितना विनम्र है।

वह खुद बहुत प्रसिद्ध होते हुए भी उन्हें ज्यादा महत्व देता है। उसी रात पंडित जी रामसेवक के घर गए और उससे क्षमायाचना की। फिर दोनों गहरे मित्र बन गए।

विचार मंथन

ब्रह्मपुत्र के बहाव रोकने चीन की भारत को धमकी

(लेखक- सनत जैन)

पाकिस्तान के पक्ष में और भारत के खिलाफ खड़ा हुआ चीन

चीन की ओर से भारत को धमकी दी गई है, वह चीन से भारत जाने वाले ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रोक सकता है। यह एक कूटनीतिक चेतावनी नहीं, बल्कि इसे चीन के रणनीतिक हथियार के रूप में देखा जाना चाहिये। यह एक बेहद गंभीर मामला है। ब्रह्मपुत्र का पानी उत्तर-पूर्व भारत के करोड़ों लोगों की जीवन रेखा है। जल जैसे प्राकृतिक संसाधन को राजनीतिक दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल करना न केवल अमानवीय है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय संधियों और पड़ोसी देशों के प्रति उत्तरदायित्व की भावना का उल्लंघन है। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोकने का जो निर्णय लिया है उसके बदले में चीन ने पाकिस्तान के समर्थन में भारत के खिलाफ यह धमकी दी है, वह भी ब्रह्मपुत्र का पानी रोक देगा। पिछले कुछ वर्षों में चीन ने जिस तरह पाकिस्तान को खुला समर्थन दिया है, वह भारत के लिए दोहरी चुनौती बन चुका है। एक ओर लद्दाख और अरुणाचल की सीमा पर चीन की आक्रामकता, दूसरी ओर पाकिस्तान को सैन्य, आर्थिक और कूटनीतिक समर्थन देकर भारत के खिलाफ अप्रत्यक्ष मोर्चा खोलना, भारत के खिलाफ चीन की एक दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है। ब्रह्मपुत्र का जल प्रवाह रोकने की धमकी उसी रणनीति का विस्तार है, जिसमें चीन जल को भी जियो-पॉलिटिकल हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। भारत को चाहिए वह इस स्थिति से सतर्क होकर बहुपक्षीय मंचों पर चीन की इस आक्रामक नीति को उजागर करे। जलवायु परिवर्तन और सीमा-पार नदियों के जल-संविधान पर आधारित अंतरराष्ट्रीय संधियों का हवाला देते हुए चीन पर कूटनीतिक दबाव बनाया जाए। भारत को अपनी उत्तर-पूर्वी जलनीति को और अधिक सुदृढ़ करना होगा, जिसमें जल संग्रहण, पुनर्चक्रण और स्थानीय जल संसाधनों का दोहन शामिल हो। यह भी आवश्यक है, भारत अपने पारंपरिक सहयोगियों जापान, अमेरिका और एसियान देशों के साथ मिलकर एक व्यापक रणनीति बनाए। जो केवल सीमा सुरक्षा तक सीमित न हो, वरन जल, साइबर और तकनीकी मोर्चों पर भी एक जुटता के साथ तैयार रहें। ब्रह्मपुत्र कोई सामरिक हथियार नहीं, बल्कि प्रकृतिजन्य, सभी जीवों और मानव के लिए प्रकृति का उपहार है। यदि चीन उसे हथियार बनाना चाहता है तो यह केवल भारत ही नहीं बल्कि समूचे एशिया के लिए खतरे की घंटी है। भारत को संयम के साथ ठोस नीति और दृढ़ता से जवाब देना होगा। ताकि जल को हथियार बनाने की इस खतरनाक प्रवृत्ति पर रोक लगाई जा सके। चीन को यह मौका भारत ने ही दिया है। इस दिशा में भारत को भी गंभीरता के साथ चिंतन मनन करना चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ भारत में जो लड़ाई शुरू की थी उसमें जल संधि को ना मानते हुए पाकिस्तान का पानी रोकने की पहल भारत ने की थी, परिणाम स्वरुप चीन जैसे देशों को भी भारत के ही निर्णय को आधार मानकर भारत को घेरने की कोशिश की जा रही है। भारत सरकार ने इसकी गंभीरता पर ध्यान ना देते हुए जो निर्णय लिया है वह भी एक तरह से अमानवीय है। कूटनीति और विदेश नीति के मामले में भारत जिस तरीके से बिना सोचे-समझे निर्णय ले रहा है, जिस तरह की धमकियां पिछले कुछ वर्षों में भारतीय मीडिया और भारत के राजनेताओं द्वारा अन्य देशों के बारे में समय-समय पर दी जा रही हैं, उसके कारण भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ भी संबंध खराब हुए हैं। चीन ने इसका लाभ उठाया है। भारत के सभी पड़ोसी देशों के साथ चीन ने व्यापारिक और सामरिक संबंधों को बढ़ाया है। भारत के लिए चुनौतियां बढ़ाई हैं। चीन भारत के कब्जे वाले पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार अशांति फैलाने का काम कर रहा है। चीन ने पिछले वर्षों में सीमावर्ती राज्यों में बड़े पैमाने पर अपनी गतिविधियां बढाकर भारत के लिए कड़ी चुनौती पैदा कर दी है। भारत के मीडिया ने तो गजब ही कर दिया है। झूठी और धमकी वाली खबरों को दिखाकर भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कमजोर करने का काम किया है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार माध्यम के इस युग में, जिस तरह से भारतीय मीडिया काल्पनिक खबरों को फैलाने का काम करता है, उसको लेकर पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध पिछले एक दशक में बड़ी तेजी के साथ खराब हुए हैं। भारत को बार-बार विश्व- गुरु के रूप में स्थापित करने और भारत की तीसरी और चौथी अर्थव्यवस्था को लेकर जो दावे भारत सरकार के हवाले से भारतीय मीडिया द्वारा किए जाते हैं, उसके कारण दुनिया के बड़े देशों के साथ भारत ने अपनी प्रतिस्पर्धा को बढ़ा लिया है।

भारत में कोरोना के नए सब-वैरिएंट्स ने बढ़ाई चिंता, 24 घंटे में 4 की मौत 685 आए नए मामले

नई दिल्ली।

भारत में कोरोना के नए सब-वैरिएंट्स ने चिंता बढ़ा दी है। पिछले 24 घंटे में 4 लोगों की मौत हुई है और 685 नए मामले आए हैं। सबसे ज्यादा सक्रिय मामले केरल (1,336), महाराष्ट्र (467), दिल्ली (375), गुजरात (265), कर्नाटक (234), पश्चिम बंगाल (205), तमिलनाडु (185) और उत्तर प्रदेश (117) में हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार, शनिवार, 31 मई तक देश में 3,395 सक्रिय मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटों में 685 नए मामले सामने आए हैं, जबकि चार लोगों की मौत हुई है। इनमें से एक-एक मौत दिल्ली, केरल, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में हुई है।

दिल्ली में 375 सक्रिय मामले हैं, जो पिछले दिन की तुलना में 81 ज्यादा हैं। यहां एक 71 वर्षीय व्यक्ति की निमोनिया, सेप्टिक शॉक और तीव्र किडनी की समस्या के कारण मृत्यु हुई। वहीं, महाराष्ट्र में 43 नए मामले दर्ज किए गए। कर्नाटक में बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में 63 वर्षीय व्यक्ति की कोविड-19 और अन्य बीमारियों के कारण मृत्यु हो गई। कर्नाटक सरकार ने स्कूलों के जल्द खुलने को देखते हुए अभिभावकों से अपील की है कि बुखार, खांसी या सर्दी के लक्षण दिखने पर बच्चों को स्कूल न भेजें। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों से घबराने की बजाय सावधानी बरतने की सलाह दी है। ज्यादातर मामले हल्के हैं, और पिछले 24 घंटों में 265 मरीज अस्पतालों से डिस्चार्ज हुए हैं। टीकाकरण को सबसे प्रभावी सुरक्षा माना जा रहा है। भीड़भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनने की सलाह दी गई है, खासकर बुजुर्गों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए। कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन, एंटीबायोटिक्स और अन्य दवाओं की तैयारी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। हाल के मामलों में उछाल का कारण दो नए सब-वैरिएंट्स एनबी.1.8.1 और एलएफ.7 को माना जा रहा है। ये वैरिएंट्स पुराने स्ट्रेन से जेनेटिक रूप से अलग हैं और इम्यून सिस्टम को चकमा देने की क्षमता रखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इन्हें 'वैरिएंट्स अंडर मॉनिटरिंग' की श्रेणी में रखा है, क्योंकि ये चीन, ताइवान, हांगकांग और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में तेजी से फैल रहे हैं। हालांकि, इनसे बीमारी की गंभीरता बढ़ने के सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन इनकी तेजी से फैलने की क्षमता ने स्वास्थ्य अधिकारियों को सतर्क कर दिया है।

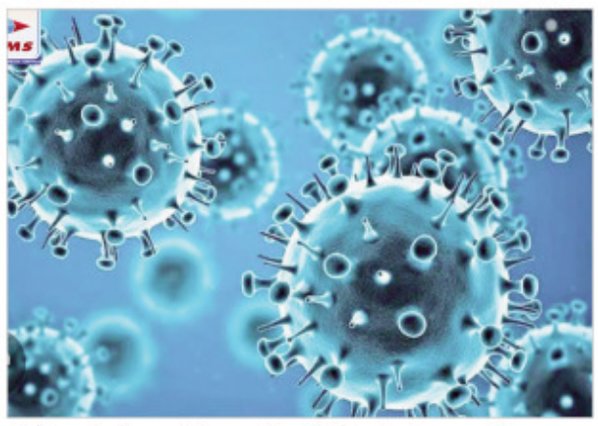

सीडीएस ने भी माना विमान गिराए गए फिर भी हमें देशद्रोही कहा जा रहा

पवन खेड़ा ने कहा- किन परिस्थितियों में सीजफायर हुआ सरकार को देना होगा जवाब

नई दिल्ली।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने ऑपरेशन सिंदूर पर सीडीएस जनरल अनिल चौहान के एक बयान को आधार बनाकर केंद्र सरकार पर रविवार को निशाना साधा। पवन खेड़ा ने कहा कि देश की जनता को यह जानने का हक है कि किन परिस्थितियों में भारत-पाक के बीच सीजफायर हुआ। उन्होंने कहा कि हम लगातार जो सवाल उठा रहे हैं, उसके कारण हमें देशद्रोही कहा जा रहा है। अब तो सीडीएस ने भी विदेश जाकर स्वीकार कर लिया है कि हमारे विमान गिराए गए। पवन खेड़ा ने कहा कि देश को यह जानने का अधिकार है कि किन परिस्थितियों में ऐसा हुआ। इसके क्या कारण थे और इसका समाधान क्या है। भारत-पाक के बीच इतनी जल्दी सीजफायर क्यों किया गया, जबकि हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान को घुटने पर लाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सवाल यह है कि केंद्र सरकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इतना क्यों डरती है। केंद्र सरकार से सारे सवाल पूछे जाएंगे और उन्हें जवाब देना होगा। इसलिए, कांग्रेस पार्टी संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर पर क्रेडिट लेने के एक सवाल पर पवन खेड़ा ने कहा कि पीएम मोदी ट्रंप के आंखों में आंख मिलाकर क्यों नहीं कहते हैं कि सीजफायर को लेकर मध्यस्थता की बात झूठी है। पूरा देश पीएम मोदी के साथ खड़ा हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के बयान पर पवन खेड़ा ने कहा कि आने वाले दिनों, हफ्तों और महीनों में बहुत कुछ होने वाला है। पीएम मोदी को तैयार रहना चाहिए और सीट बेल्ट बांधकर बैठ जाना चाहिए। खेड़ा का दावा है कि बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले कई समीकरण बदलेंगे। वहीं, चिराग पासवान के चुनाव लड़ने पर आरएलडी नेता मलूक नागर ने कहा कि यह अच्छी बात है वह बड़े नेता हैं। वह चुनाव लड़ते हैं तो एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी। चिराग बिहार में चुनाव लड़ेंगे तो उनकी पार्टी को ही मजबूती मिलेगी।

वेतन आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति के बचे सिर्फ 7 माह

नई दिल्ली।

केंद्र की मोदी सरकार ने इस साल जनवरी में 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी थी और उसके बाद संबंधित अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श शुरू हुआ था। ताकि संदर्भ की शर्तों (टीओआर) को अंतिम रूप दे सके और संभावित आयोग के सदस्यों के काम शुरू करने के तौर-तरीकों को अंतिम रूप दिया जा सके।

हालांकि, केंद्र ने अभी तक आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। पिछले महीने सर्कुलर जारी था जिसमें प्रतिनियुक्ति के आधार पर लगभग 35 पदों को भरने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव के बारे में जानकारी दी गई थी।

इन पदों को भरने के लिए योग्य सरकारी कर्मचारियों से आवेदन मांगे गए थे। तब से, मीडिया में टीओआर को अंतिम रूप देने और सदस्यों की नियुक्तियों के बारे में अटकलें लगाने वाली कई रिपोर्टें आई हैं।

दरअसल मई का महीना खत्म हो गया है और इसके बाद 1 जनवरी 2026 की डेडलाइन पर इस लागू होने में सिर्फ 7 महीने शेष हैं।

मौजूदा 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है। अब तक की प्रगति को देखकर कहना मुश्किल है कि सरकार 8वें वेतन आयोग को समय पर लागू कर पाएगी।

इसके बाद 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना काफी कम है। अब सवाल उठता है कि अगर कोई कर्मचारी 1 जनवरी 2026 या उसके बाद रिटायर होता है, लेकिन तब तक 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू नहीं हुई हैं, तब क्या उन्हें इसका लाभ मिलेगा? इसका जवाब है हां। इसतरह के सभी कर्मचारियों को एरियर के रूप में वेतन संशोधन का लाभ भी मिलेगा। ऐसा पहले भी हो चुका है। 7वें वेतन आयोग के समय करीब एक साल की देरी हुई थी, लेकिन सभी कर्मचारियों और पेंशनरों को बकाया दिया गया था।

देश के गद्दारों को कोने-कोने में ढूंढ रही एनआईए, 8 राज्यों में 15 ठिकानों पर दी दबिश

नई दिल्ली।

देश को गद्दारों को कोने कोने से एनआईए निकालने में जुटी है। शनिवार को एनआईए ने पाकिस्तान से जुड़े एक जासूसी रैकेट की जांच के तहत देशभर के 8 राज्यों में 15 ठिकानों पर छापेमारी की।

जिन राज्यों में ये छापे पड़े, उनमें दिल्ली, महाराष्ट्र (मुंबई), हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, असम और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। ये छापेमारी उन लोगों के घरों और ठिकानों पर की गई जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से जुड़े होने के शक में हैं। सीआरपीएफ के जवान को जासूसी के आरोप में पकड़े जाने के बाद अब इस मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने कमान संभाल ली है। एनआईए के मुताबिक, छापों के दौरान एजेंसी को कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, गोपनीय दस्तावेज और संदिग्ध आर्थिक लेन-देन के रिकॉर्ड मिले हैं। अब इन सभी सामग्रियों की बारीकी से जांच की जा रही है ताकि इस जासूसी नेटवर्क की जड़ तक पहुंचा जा सके।

मामला उस वक्त सामने आया जब सीआरपीएफ के एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोती राम जाट को गोपनीय जानकारी लीक करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। एनआईए की जांच में पता चला कि मोती राम साल 2023 से पाकिस्तान के एजेंटों को संवेदनशील जानकारी दे रहा था और इसके बदले में उसे भारत के अलग-अलग माध्यमों से पैसे भी मिलते थे।

सीआरपीएफ ने उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। इस पूरे मामले की जांच एनआईए कर रही है और केस भारतीय न्याय संहिता, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और यूएपीए के तहत दर्ज किया गया है।

सिक्किम में लगातार बारिश और भूस्खलन से रास्ते बंद करीब 1,500 पर्यटक फंसे

मंगन।

सिक्किम में लगातार बारिश और भूस्खलन के कारण मुख्य मार्ग के बाधित होने से उत्तर सिक्किम के विभिन्न हिस्सों में करीब 1,500 पर्यटक फंस गए। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि दूसरी ओर भारी बारिश के कारण लापता आठ पर्यटकों की तलाश में बाधा आई और तीस्ता नदी में जलस्तर बढ़ने के बाद अंततः तलाशी अभियान रोकना पड़ा है। मंगन जिले में तीस्ता नदी में एक वाहन के गिर जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए, जबकि आठ अन्य लापता हैं। लाचेन-लाचुंग राजमार्ग पर मुन्सिथांग के पास यह वाहन 1,000 फुट से अधिक गहराई में नदी में गिर गया था।

मंगन के पुलिस अधीक्षक (एसपी) सोनम देचू भूटिया ने बताया कि लाचेन में 115 पर्यटक और लाचुंग में 1,350 पर्यटक फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा, ''कई स्थानों पर भूस्खलन के कारण दोनों ओर से निकलने के रास्ते बंद है, इसलिए पर्यटकों को अपने होटलों में ही ठहरने की सलाह दी गई है और सड़कें पूरी तरह खुल जाने के बाद उन्हें स्थानांतरित कर दिया जाएगा।''

अधिकारियों ने बताया कि रविवार तक पेयजल आपूर्ति बहाल करने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने बताया कि करीब 24 घंटे बाद अपराह्न लगभग तीन बजे मोबाइल नेटवर्क सेवाएं बहाल हो सकी।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र में बादल फटने से हुई भारी वर्षा के कारण तीस्ता नदी का जलस्तर बढ़ गया है। उन्होंने कहा, ''आज कोई पर्यटक परमिट जारी नहीं किया गया है और कल भी उत्तर सिक्किम जाने के लिए परमिट जारी नहीं किया जाएगा।''

एक ही मंच पर इतनी सुंदरता, गरिमा और खूबसूरत दिल दिखे

अभिनेत्री नम्रता शिरोडकर ने की मिस वर्ल्ड प्रतियोगियों की तारीफ

मुंबई।

1993 में फेमिना मिस इंडिया बनी अभिनेत्री नम्रता शिरोडकर ने मिस वर्ल्ड 2025 की सभी प्रतियोगियों के लिए खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि एक ही मंच पर इतनी सुंदरता, गरिमा और खूबसूरत दिल दिखाई दिए। इसके साथ ही उन्होंने मिस थाईलैंड ओपल सुचाता चुआंगसरी को 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जीतने पर बधाई दी।

नम्रता ने मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष और सीईओ जूलिया मोर्ले से मुलाकात की और कहा कि उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। नम्रता ने अपने इंस्टाग्राम पर इवेंट की कई तस्वीरें शेयर कीं हैं, जिनमें वह जूलिया मोर्ले, सोनू सूद और मानुषी छिल्लर के साथ दिख रही हैं। उन्होंने कैप्शन में लिखा- एक ही मंच पर इतनी सुंदरता, गरिमा और खूबसूरत दिल दिखाई दिए। सभी अद्भुत प्रतियोगियों को बधाई। आप सब बहुत ही शानदार थे।

उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा- वाह, क्या जादुई शाम थी! जूलिया मोर्ले से मिलकर बहुत अच्छा लगा। मिस वर्ल्ड 2025 की जीत के लिए मिस थाईलैंड ओपल सुचाता चुआंगसरी को बहुत-बहुत शुभकामनाएं!

इस साल मिस वर्ल्ड 2025 का आयोजन हैदराबाद में किया गया। इसमें दुनियाभर से करीब 108 प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया। भारत की ओर से मॉडल नंदिनी गुप्ता ने इसमें हिस्सा लिया। हालांकि, वे मिस वर्ल्ड 2025 के खिताब की दौड़ में टॉप-20 तक ही जगह बना पाई।

चेक गणराज्य की मौजूदा मिस वर्ल्ड क्रिस्टीना पिस्जकोवा ने अपना ताज नई मिस वर्ल्ड चुआंगसरी को सौंपा। चुआंगसरी ने कहा कि यह मेरे लिए बहुत बड़ी सफलता है। थाईलैंड को मिस वर्ल्ड के मंच पर पहचान मिलने पर मुझे गर्व है। यह हमारा पहला मिस वर्ल्ड का ताज है और हमने इसे पाने के लिए 70 साल से ज्यादा इंतजार किया है।

जासूसी मामले में एनआईए ने राजस्थान समेत 8 राज्यों में मारे छापे

सीआरपीएफ एएसआई मोतीराम जाट मामले में छापेमारी

पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी पीआईओस से कनेक्शन, अहम दस्तावेज जब्त

जयपुर।

पाकिस्तान से जुड़े जासूसी मामले में एनआईए ने बड़ा एक्शन लिया है। एनआईए ने देश के आठ राज्यों में फैले 15 ठिकानों पर एक साथ छापे मारे। ये छापेमारी दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, असम और पश्चिम बंगाल में की गई, जिन लोगों के यहां छापे मारे गए उनका संबंध पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी पाक इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स (पीआईओस) से बताया जा रहा है।

सीआरपीएफ के एएसआई मोतीराम जाट जिसे हाल में एनआईए ने गिरफ्तार किया था जासूसी मामले में उसी मामले में छापा मारा है। मोतीराम जाट को 20 मई को एनआईए ने गिरफ्तार किया था। मोतीराम जाट पहलगाम हमले से पहले वहीं पोस्टेड था। हमले से पांच दिन पहले एएसआई मोतीराम जाट का पहलगाम से ट्रांसफर किया गया था। मोतीराम की पहलगाम हमले में भूमिका का अभी पता नहीं चल सका है। एनआईए के डीजी ने बताया है कि अभी तक की जांच में इसका पहलगाम हमले से कोई कनेक्शन सामने नहीं आया है।

छापेमारी में एनआईए की टीमों ने कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़, संदिग्ध दस्तावेज़ और कुछ अहम फाइनेंशियल कागजात बरामद किए हैं। ये सब जांच के लिए एनालाइज किए जा रहे हैं, ताकि इस पूरे जासूसी नेटवर्क का पता लगाया जा सके। एनआईए की जांच में सामने आया है कि जिन लोगों के यहां छापे मारे गए हैं, उनका सीधा कनेक्शन पाकिस्तान में बैठे ऑपरेटिव्स से था। ये लोग जासूसी के लिए फाइनेंशियल चैनल के तौर पर काम कर रहे थे।

इस मामले में एनआईए ने 20 मई को मामला दर्ज किया था। इससे पहले एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया था जो 2023 से पाकिस्तान को संवेदनशील जानकारी भेज रहा था। इसके बदले उसे भारत में कई सोर्सेस से पैसे मिल रहा था। अब इस मामले में एनआईए ने और कड़ियां जोड़ते हुए ये छापेमारी की। मामले में कई धाराओं के तहत जांच चल रही है।

मीडिया रिपोर्ट में एनआईए सूत्रों के मुताबिक जासूसी के शक में राजस्थान के तीन जगहों पर छापेमारी की गई है।

हालांकि, ये साफ नहीं है कि टीमें किन शहरों में पहुंची हैं। राजस्थान के अलावा दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, असम और पश्चिम बंगाल राज्यों में 15 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। संदिग्धों के घरों, कार्यालयों में दबिश दी गई है। तलाशी के दौरान एनआईए की टीम को कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, पैसों का ट्रांजैक्शन, मोबाइल कॉल डिटेल, मोबाइल से फोटो और मैसेज रिकवर हुए हैं। इस दौरान गिरफ्तार किए गए लोगों से पूछताछ जारी है।

पहले ईडी अब आयकर विभाग के वरिष्ठ अधिकारी को रिश्वत लेते पकड़ा, सीबीआई की करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति

नई दिल्ली।

भ्रष्टाचार के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई का शिकंजा लगातार कस रहा है। पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के एक अधिकारी को गिरफ्तार किया और अब आयकर विभाग के एक वरिष्ठ आईआरएस अधिकारी को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने जिस अधिकारी को गिरफ्तार किया है, उनका नाम अमित कुमार सिंघल है। वे 2007 बैच के आईआरएस अधिकारी हैं। वर्तमान में वे नई दिल्ली स्थित आयकर सेवा निदेशालय में सीनियर एडिशनल डायरेक्टर जनरल के पद पर तैनात थे। सीबीआई के अनुसार, सिंघल ने एक शिकायतकर्ता से 25 लाख रुपये की रिश्वत की मांगी थी। यह रकम कथित तौर पर एक कारोबारी के टैक्स मामलों में मदद करने के लिए मांगी गई थी। सीबीआई ने योजना बनाकर सिंघल को रिश्वत लेकर रंगे हाथों पकड़ा। मामले में केवल अधिकारी ही नहीं, बल्कि निजी व्यक्ति हर्ष कोटक को भी गिरफ्तार किया है। हर्ष कोटक इस घूसखोरी में बिचौलिए की भूमिका में था। यह गिरफ्तारी तब हुई है, जब हाल ही में सीबीआई ने ईडी के एक अधिकारी को भी भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया था। इसमें सीबीआई की ये लगातार कार्रवाई करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का संकेत देती है। घटनाक्रम न केवल प्रशासनिक जवाबदेही को बल देता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि सरकारी सिस्टम में खुद-सुधार की प्रक्रिया सक्रिय है।

संक्षिप्त समाचार

भारतीय तटरक्षक बल ने अस्वस्थ कैप्टन को सुरक्षित रूप से निकाला

नई दिल्ली। भारतीय तटरक्षक बल ने मध्य रात्रि में मानवीय सहायता प्रदान करते हुए समुद्र में बहामास के ध्वज वाले एक जहाज से अस्वस्थ कैप्टन को सुरक्षित रूप से निकाला। भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) ने पोस्ट में कुछ तस्वीरें साझा कर यह जानकारी दी। इसमें बताया गया कि आधी रात को बचाव अभियान में भारतीय तटरक्षक बल स्टेशन (काकीनाडा) ने एक जीवन रक्षक चिकित्सा निकासी अभियान का समन्वय किया। आईसीजीएस 430 ने 1 बजकर 10 मिनट पर बहामास के ध्वज वाले जहाज से अस्वस्थ कैप्टन को सुरक्षित रूप से निकाला, जिन्हें दिल का दौरा पड़ा था। मरीज को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है।

बरेली में मामूली विवाद में युवक की चाकू घोंपकर हत्या

बरेली। यूपी के बरेली जिले के बारादरी थाना क्षेत्र के काकरटोला इलाके में मामूली कहासुनी ने हिंसक झड़प में बदल गई। जिसमें 30 वर्षीय एक व्यक्ति की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान अरशद उर्फ गुड्डू के रूप में हुई है। यह विवाद कुछ दिन पहले बारावफात जुलूस के दौरान पुरस्कार वितरण को लेकर हुआ है। यह विवाद बढ़ गया और दोनों पक्षों के बीच हाथापाई की नौबत आ गई। झगड़े के दौरान एक गुट के आमिर नामक व्यक्ति ने कथित तौर पर चाकू निकाला और अरशद पर कई वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस अधिकारी ने कहा, मामले की जांच शुरू कर दी गई है। फरार आरोपी आमिर की तलाश में पुलिस की टीमें संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं। आमिर को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। स्थानीय लोगों ने घायल अरशद को तुरंत पास के निजी अस्पताल पहुंचाया। हालांकि, डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद, गंभीर चोटों के कारण उसकी मौत हो गई। अरशद की मौत की खबर फैलते ही अस्पताल के बाहर बड़ी संख्या में भीड़ जमा हो गई।

चार राज्यों के 380 बीएड कॉलेजों की मान्यता रद्द

मध्य प्रदेश के 11 बीएड कॉलेज

भोपाल। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा चार राज्यों के 380 बीएड कॉलेज की मान्यता समाप्त की गई है। इसमें सबसे अधिक 296 बीएड कॉलेज महाराष्ट्र के हैं। मध्य प्रदेश के 11 राजस्थान और छत्तीसगढ़ के 74 बीएड कॉलेज शामिल हैं। मध्य प्रदेश के जिन बीएड कॉलेज की मान्यता समाप्त की गई है। उनमें मध्य प्रदेश सरकार का राजा भोज ओपन विश्वविद्यालय भी शामिल है। विश्वविद्यालय डिस्टेंस लर्निंग बीएड प्रोग्राम के तहत हर साल 1000 सीटों पर छात्रों को प्रवेश देता था। इसके अलावा सांई नाथ महाविद्यालय, ग्वालियर का ऋषि कुल ग्रुप आफ बीएड कॉलेज, फरीदा एजुकेशन सोसाइटी, रीवा का अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, नीराचलम शिक्षा महाविद्यालय सतना, स्वामी नारायणदास शिक्षा कॉलेज सागर के पंडित बीडी मेमोरियल बीएड कॉलेज तथा द्रोणाचार्य अकैडमी की मान्यता भी समाप्त हो गई है।

10 रूटों पर चलाई जाएगी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन

ट्रेनों का निर्माण बीईएमएल कंपनी को सौंपा गया

नई दिल्ली। भारतीय रेल के यात्रियों को न केवल दिन के समय, बल्कि रात के समय में भी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का आनंद लेने का मौका मिलेगा। रेलवे मंत्रालय ने घोषणा की है कि 2025-26 वित्तीय वर्ष में देशभर में 10 नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें शुरू की जाएंगी। इन ट्रेनों का निर्माण बीईएमएल कंपनी को सौंपा गया है, और इन्हें इस वर्ष के अंत तक पटरियों पर उतारने की योजना बनाई गई है। इन ट्रेनों की तकनीकी और सुविधाएँ वर्ल्ड क्लास होगी, जिससे यात्रियों को किसी भी तरह की कमी न महसूस हो। इन ट्रेनों के रूट का औपचारिक एलान अभी तक नहीं किया गया है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि ये ट्रेनें देश के व्यस्त और लंबी दूरी वाले मार्गों पर चलाई जा सकती हैं। इन आधुनिक ट्रेनों का निर्माण तीन बड़ी कंपनियों ने किया है, जिसमें बीईएमएल, काइनेट रेलवे सॉल्यूशंस लिमिटेड और टिटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड-बीएचईएल कंसोर्टियम शामिल हैं। इन नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों का इंटीरियर भी यात्रियों को प्रीमियम फील देगा, और ये ट्रेनें ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील से बनी होंगी।

पहला कॉलम

वे स्वदेशी परियोजनाएं जिनकी देरी से नाराज हुए वायुसेना प्रमुख, देश की सुरक्षा के लिए खतरा

नई दिल्ली।

भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफमार्शल अमर प्रीत सिंह ने रक्षा खरीद परियोजनाओं में देरी पर गहरी नाराजगी और चिंता जाहिर की है। एयर चीफ मार्शल सिंह का इशारा विशेष रूप से स्वदेशी परियोजनाओं की ओर था। उन्होंने कहा कि उनकी जानकारी में एक भी प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं हुआ है। आइए जानते हैं इन प्रोजेक्ट्स की मौजूदा स्थिति और देरी के कारणज

तेजस एमके-1ए

हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के साथ फरवरी 2021 में 83 एलसीए एमके-1ए विमानों के लिए 48,000 करोड़ रुपये का समझौता हुआ था। ये 4.5 जेनरेशन के हल्के लड़ाकू विमान हैं, जो भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन शक्ति बढ़ाने के लिए जरुरी हैं। मुख्य रूप से जनरल इलेक्ट्रिक (जीई) से एफ404 इंजनों की आपूर्ति में देरी के कारण इसका उत्पादन डिले हुआ है। विनिर्माण कंपनी एचएएल ने तकनीकी और सप्लाई चेन की समस्याओं का भी हवाला दिया है। समझौते के अनुसार पहला विमान मार्च 2024 तक डिलीवर होना था, लेकिन अभी तक एक भी विमान नहीं मिला है। एचएएल ने आश्वासन दिया है कि तकनीकी समस्याएं सुलझाई गई हैं और जल्द ही डिलीवरी शुरू होगी। फिलहाल अभी तक करीब 14 महीने से अधिक की देरी हो चुकी है। इसकी वजह से भारतीय वायु सेना की स्क्वाड्रन संख्या में कमी के बीच यह देरी हवाई युद्ध क्षमता पर गंभीर प्रभाव डाल सकती है।

तेजस एमके-2

तेजस एमके-2, एलसीए एमके-1ए का एडवांस एडीशन है। इस अधिक शक्तिशाली जीई एफ414 इंजन और बेहतर एवियोनिक्स के साथ डिजाइन किया गया है। इसका प्रोटोटाइप अभी तक तैयार नहीं हुआ है, जो डिजाइन और विकास में देरी का मुख्य कारण है। प्रोजेक्ट अभी प्रारंभिक डिजाइन और विकास चरण में है। प्रोटोटाइप का निर्माण शुरू नहीं हुआ है और उत्पादन शुरू होने में कई साल लग सकते हैं। इसके लिए कोई स्पष्ट समयसीमा नहीं दी गई थी। लेकिन एयर चीफ मार्शल ने इसकी धीमी प्रगति पर निराशा जाहिर की है।

एएमसीए स्टील्थ फाइटर जेट

एएमसीए पांचवीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट है। इस मोदी सरकार की 'आत्मनिर्भर भारत' पहल के तहत तैयार किया जा रहा है। यह प्रोजेक्ट भारत की एडवांस हवाई युद्ध क्षमता के लिए महत्वपूर्ण है। प्रोटोटाइप का निर्माण अभी तक शुरू नहीं हुआ है। डिजाइन, तकनीकी विकास, और अंतरराष्ट्रीय सहयोग (जैसे इंजन आपूर्ति) में देरी प्रमुख कारण हैं। हाल ही में केंद्र ने एएमसीए के विकास के लिए योजना को मंजूरी दी है, लेकिन प्रोटोटाइप और उत्पादन अभी दूर की बात है। समयसीमा स्पष्ट नहीं है, लेकिन प्रोजेक्ट अपनी शुरुआती योजना से काफी पीछे है। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि देरी के कारण वायु सेना की स्क्वाड्रन शक्ति 42 से घटकर करीब 30 तक पहुंच गई है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, खासकर जब पड़ोसी देश जैसे चीन अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा रहे हैं। वायुसेना प्रमुख सिंह ने 'मेक इन इंडिया' पहल का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि सेना और इंडस्ट्री के बीच बेहतर तालमेल और विश्वास की जरूरत है। लेकिन देरी इस पहल की विश्वसनीयता को प्रभावित कर रही है। वहीं तेजस एमके-1ए की डिलीवरी में हो रही देरी को लेकर रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन हुआ है। यह समिति उत्पादन में अड़चनों की पहचान करेगी और समाधान बताएगी। वहीं, एचएएल के चेयरमैन डी.के.सुनील ने स्वीकार किया कि देरी हुई है। लेकिन उन्होंने इंडस्ट्री की सुस्ती के बजाय तकनीकी और सप्लाई चेन की समस्याओं का परिणाम बताया। उन्होंने कहा हैं कि सुचारू तौर पर इंजन सप्लाई होने पर डिलीवरी शुरू होगी।

सिक्किम में लगातार बारिश और भूस्खलन से रास्ते बंद करीब

1,500 पर्यटक फंसे

मंगन।

सिक्किम में लगातार बारिश और भूस्खलन के कारण मुख्य मार्ग के बाधित होने से उत्तर सिक्किम के विभिन्न हिस्सों में करीब 1,500 पर्यटक फंस गए। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि दूसरी ओर भारी बारिश के कारण लापता आठ पर्यटकों की तलाश में बाधा आई और तीस्ता नदी में जलस्तर बढ़ने के बाद अंततः तलाशी अभियान रोकना पड़ा है। मंगन जिले में तीस्ता नदी में एक वाहन के गिर जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए, जबकि आठ अन्य लापता हैं। लाचेन-लाचुंग राजमार्ग पर मुन्सिथांग के पास यह वाहन 1,000 फुट से अधिक गहराई में नदी में गिर गया था। मंगन के पुलिस अधीक्षक (एसपी) सोनम देचू भूटिया ने बताया कि लाचेन में 115 पर्यटक और लाचुंग में 1,350 पर्यटक फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा, ''कई स्थानों पर भूस्खलन के कारण दोनों ओर से निकलने के रास्ते बंद है, इसलिए पर्यटकों को अपने होटलों में ही ठहरने की सलाह दी गई है और सड़कें पूरी तरह खुल जाने के बाद उन्हें स्थानांतरित कर दिया जाएगा।''

अधिकारियों ने बताया कि रविवार तक पेयजल आपूर्ति बहाल करने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने बताया कि करीब 24 घंटे बाद अपराह्न लगभग तीन बजे मोबाइल नेटवर्क सेवाएं बहाल हो सकी।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र में बादल फटने से हुई भारी वर्षा के कारण तीस्ता नदी का जलस्तर बढ़ गया है। उन्होंने कहा, ''आज कोई पर्यटक परमिट जारी नहीं किया गया है और कल भी उत्तर सिक्किम जाने के लिए परमिट जारी नहीं किया जाएगा।''

ममता बनर्जी ने बंगाल को बनाया घुसपैठ, भ्रष्टाचार, स्त्रियों पर अत्याचार का केंद्र, हिंदुओं के साथ हुआ दुराचार : अमित शाह

कोलकाता।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में विजय संकल्प कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर राज्य में भ्रष्टाचार, हिंसा और घुसपैठ को बढ़ावा देने का आरोप लगाया।

अमित शाह ने कहा कि वर्षों तक बंगाल ने हर क्षेत्र में देश का नेतृत्व किया है। कई वर्षों तक यहां कम्युनिस्टों का भी शासन रहा। उसके बाद ममता दीदी ने आकर इस भूमि को घुसपैठ, भ्रष्टाचार, अपराध और हिंदुओं पर अत्याचार का केंद्र बना दिया।

उन्होंने कहा कि वन्दे मातरम् के रचयिता महान बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की इस भूमि ने वर्षों तक देश का मार्गदर्शन किया। ज्ञान, धर्म, स्वतंत्रता संग्राम समेत हर क्षेत्र में देश का नेतृत्व करने वाले बंगाल में कई साल तक कम्युनिस्टों का शासन रहा। उसके बाद मां, माटी, मानुष का नारा देकर सत्ता में आने वाली ममता बनर्जी ने महान बंग भूमि को आज घुसपैठ, भ्रष्टाचार, स्त्रियों पर अत्याचार, अपराध, बम धमाकों और हिंदुओं के साथ दुराचार का केंद्र बनाकर रख दिया है।

उन्होंने कहा कि बंगाल की इसी धरती पर चुनाव के दौरान और तृणमूल कांग्रेस के चुनाव जीतने के बाद भाजपा के अनेक कार्यकर्ताओं की हत्या की गई। पूरे देश में चुनाव के दौरान हिंसा खत्म हो गई होगी, लेकिन बंगाल में हिंसा जारी है।

केंद्रीय गृह मंत्री ने तृणमूल सुप्रीमो को चुनौती देते हुए कहा, दीदी, हिंसा करने वालों को आप कब तक बचाती रहेंगी? आपका समय पूरा हो गया है और 2026 में पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। पिछले 10 वर्षों में पश्चिम बंगाल सरकार को जारी किए गए 8,27,000 करोड़ रुपए यूपीए की तुलना में चार गुना अधिक हैं। हमारा फोकस प्रदेश का विकास है। हमें भरोसा है कि प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का अवसर जरूर देगी।

उन्होंने मुख्यमंत्री को ललकारते हुए कहा, हिम्मत हो तो बिना हिंसा के चुनाव कराकर देखिए, आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। उन्होंने ममता बनर्जी पर ऑपरेशन सिंदूर का विरोध कर देश की करोड़ों माताओं-बहनों के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया और राज्य की महिलाओं से चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को सिंदूर की कीमत समझा देने की अपील की।

अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जिक्र करते हुए कहा कि सेना ने पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर जाकर आतंकवादियों के मुख्यालयों पर हमला किया। इसमें कई आतंकवादी मारे गए, लेकिन लगता है कि ममता बनर्जी को इससे परेशानी हो रही है। उन्होंने ऑपरेशन का विरोध एक खेदजनक बयान के माध्यम से न केवल मिशन का विरोध किया, बल्कि देश की महिलाओं की भावनाओं का भी अनादर किया।

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि बंगाल का चुनाव सिर्फ बंगाल के भविष्य को ही नहीं तय करता है, बल्कि यह देश की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए बंगाल की सीमाओं को बांग्लादेशियों के लिए खुला छोड़ दिया है। उनके आशीर्वाद से बंगाल में घुसपैठ हो रही है। उन्होंने कहा कि यह घुसपैठ सिर्फ भाजपा की सरकार रोक सकती है क्योंकि मुख्यमंत्री का ध्यान देश की सीमा की सुरक्षा से अधिक अपने भतीजे (अभिषेक बनर्जी) का भविष्य सुरक्षित करने पर है।

अमित शाह ने कहा कि विकास को बढ़ावा देने के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दशकों से पश्चिम बंगाल के लोग बंगाली को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दिलाने की वकालत कर रहे थे। हालांकि ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार का समर्थन किया, लेकिन वह बंगाली को लंबे समय से प्रतीक्षित मान्यता दिलाने में असमर्थ रहीं। हालांकि पीएम मोदी के नेतृत्व में बंगाली भाषा को अंततः शास्त्रीय भाषा का प्रतिष्ठित दर्जा दिया गया।

चार प्रमुख प्रवृत्तियों से आकार लेंगे भविष्य के युद्ध : सीडीएस जनरल अनिल चौहान

नई दिल्ली।

भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान का कहना है कि भविष्य के युद्ध चार प्रमुख प्रवृत्तियों द्वारा आकार लेंगे। इनमें से एक है सभी क्षेत्रों में सेंसर्स का प्रसार। दूसरा- लंबी दूरी तक मार करने वाली हाइपरसोनिक और सटीक हथियार प्रणालियां। तीसरा, स्वायत्त प्रणालियों के साथ मानव-मानव रहित टीमिंग। चौथा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और क्वांटम तकनीक द्वारा संचालित युद्धक्षेत्र की बुद्धिमत्ता।

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान ने यह जानकारी रविवार को सिंगापुर में दी। वह यहां आयोजित प्रतिष्ठित 'शांगरी-ला डायलॉग 2025' में 'भविष्य की चुनौतियों के लिए रक्षा नवाचार समाधान' विषय पर बोल रहे थे। इस कार्यक्रम में जनरल अनिल चौहान ने बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य और तेजी से हो रहे तकनीकी परिवर्तनों पर प्रकाश डाला।

उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी के लोकतंत्रीकरण ने गैर-राज्य तत्वों (नॉन स्टेट एक्टर्स) को सशक्त किया है, जिससे प्रॉक्सी युद्धों और अस्थिरता को बढ़ावा मिला है। उन्होंने क्षमताओं के विकास के लिए अनुकूलनशीलता, नवाचार और आत्मनिर्भरता को मूलमंत्र बताया। भारत ने निजी उद्योगों के साथ सहयोग करते हुए एक संयुक्त रक्षा उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र विकसित किया है। उन्होंने

बताया कि भारत ने 'रणनीति-प्रेरित आधुनिकीकरण' को अपनाया है। इससे युद्धक प्रणालियां परिचालन आवश्यकताओं और स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप विकसित की जा सकें।

जनरल चौहान ने कहा कि वर्तमान में चल रहा परिवर्तन सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सिद्धांत, संगठनात्मक संस्कृति और मानव संसाधन का भी कायाकल्प शामिल है। उन्होंने कहा कि भारत की अनूठी भौगोलिक स्थिति, अनुभव और आकांक्षाएं इसके रक्षा दृष्टिकोण को आकार देती हैं। अपने संबोधन के अंत में, जनरल अनिल चौहान ने वैश्विक शांति और उत्तरदायी नवाचार के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया।

उन्होंने 'शांगरी-ला डायलॉग 2025' को वैश्विक स्थिरता हेतु संवाद और सहयोग को बढ़ावा देने वाला एक महत्वपूर्ण मंच बताया। 'शांगरी-ला डायलॉग 2025' के दौरान भारत और फिलीपींस के रक्षा प्रमुखों के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी हुई।

खाने की आजादी का मतलब ये कतई नहीं की आप गौमाता को काट-काट कर खाएं: अविमुक्तेश्वरानंद

वाराणसी।

दिल्ली में एक दुकान पर गौमांस मिलने की घटना पर ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने अपनी प्रतिक्रिया देकर निंदनीय बताया है। उन्होंने कहा गौमाता का मांस दिल्ली में दुकानों पर बिकता हुआ लोगों को मिल रहा है और जब लोग इसके खिलाफ आवाज उठाते है, तब कुछ लोग के लोग कह रहे है कि अन्याय हो रहा है। उन्होंने कहा ये बिल्कुल गलत बात है गौमाता हम हिंदुओं की आस्था का केंद्र हैं, वहां किसी का भोजन नहीं हो सकती। शंकराचार्य ने कहा कि भोजन की आजादी का मतलब ये नहीं है कि किसी की आस्था जिससे जुड़ी हुई हो आप उस गौमाता को काट काट कर खाने लगे। जब देश में वामपंथी अपनी विचारधारा को प्रकट करने के लिए आगे आ सकते हैं, तब सनातनी

हिंदू और गौमाता के भक्त क्यों चुप बैठे हैं? उन्हें भी आगे आकर बता देना चाहिए कि अब हम गौ माता को बोटी बोटी कटते हुए देखने को तैयार नहीं । उन्होंने दिल्ली और केंद्र सरकार से अपील कर कहा कि सरकारों को भी आगे आना चाहिए और गौ भक्तों की भावनाओं का संरक्षण करना चाहिए अन्यथा पीड़ा गहराती जाएगी जिसका कुफल ही होगा सुफल नहीं होगा।

पाक से 10 बिलियन, तो भारत से 130 बिलियन डॉलर का कारोबार कर रहा यूएस, फिर भी...

नई दिल्ली।

पाकिस्तान और अमेरिका के बीच करीब 10 बिलियन डॉलर का कोराबार होता है। इसमें से भी पाकिस्तान को यहां करीब 5 अरब डॉलर का ट्रेड सरप्लस है। ट्रंप ने पहले पाकिस्तान पर 29 प्रतिशत तक का भारी टैरिफ ठोंकने का चेतावनी दे चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के प्रतिनिधि अगले सप्ताह अमेरिका पहुंच रहे हैं ताकि दोनों देशों के बीच टैरिफ पर समझौता किया जा सके। बता दें कि यह वहीं पाकिस्तान है, जिसे दुनिया भर में आतंकवाद को पनाह देने वाले देश के तौर पर देखा जाता है। दूसरी तरफ भारत है, जो अमेरिका का रणनीतिक, आर्थिक और लोकतांत्रिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच व्यापार का आंकड़ा 130 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है, जबकि पाकिस्तान के साथ यह महज 10 बिलियन डॉलर के आसपास है। फिर भी ट्रंप की पाकिस्तान को लेकर 'नरमी' कई सवाल खड़े कर रही है।

दरअसल ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, पाकिस्तान के प्रतिनिधि अगले सप्ताह आ रहे हैं। और भारत के साथ, जैसा कि आप जानते हैं, हम एक डील के बेहद करीब हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर पाकिस्तान और भारत युद्ध के रास्ते पर चलते, तो वे किसी भी समझौते में दिलचस्पी नहीं रखते। ट्रंप ने दावा किया कि उनके कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित परमाणु युद्ध को टैरिफ डील के जरिये रोका, न कि गोलियों से। ट्रंप ने कहा, 'हमने व्यापार के जरिये इस संघर्ष को टाला। आमतौर पर ये देश गोलियों के जरिये लड़ते हैं, लेकिन हमने व्यापार के जरिये सुलह कराई।

भारतीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में वॉशिंगटन का दौरा किया है। इस दौरान भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर बातचीत को अंतिम रूप देने की कोशिशें हुईं। उम्मीद है कि जुलाई की शुरुआत तक दोनों देश किसी समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। इन तमाम तथ्यों के बावजूद ट्रंप का पाकिस्तान के प्रति उदार रुख भारत में कई लोगों को चौंका रहा है। जिस देश पर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर आतंकवाद के खुले समर्थन के आरोप लगते रहे हैं, उसके साथ व्यापार समझौते की संभावनाएं जताना, अमेरिका की प्राथमिकताओं पर सवाल खड़े करता है। तो क्या यह सब सिर्फ कूटनीतिक संतुलन साधने की रणनीति है? या फिर ट्रंप का यह रवैया उनके व्यापारिक नजरिए से जुड़ा है।

स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक एवं सम्पादक कजोड़मल मीना के लिए स्काईटक प्रिन्टर्स, 111, नवाब कल्लन का बाग, एमएलए क्वार्टर, नीयर समाचार जगत, एमआई रोड, जयपुर से मुद्रित एवं 303, भव्य टॉवर, कबीर मार्ग, बनीपार्क जयपुर से प्रकाशित।
(इस अंक में प्रकाशित समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पीआरबी एक्ट के तहत उत्तरदायी) समस्त विवादों का न्यायिक क्षेत्राधिकार जयपुर शहर होगा। मो. नं. 9928078717